Daily Current Affairs

Date : 07 July, 2026

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियाँ
2.	नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट – 2024 में राजस्थान
3.	ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना के नए दिशा-निर्देश-2026
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. सहकार वन : सुमेल गाँव 2. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम : अजमेर
5.	चांगपा समुदाय
6.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
7.	क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)– संशोधित UDAN लॉन्च
8.	भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA)
9.	हायाबुसा2 मिशन
10.	सब-ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स (SOLVE)
11.	वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राजस्थान परिदृश्य

सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियाँ

चर्चा में क्यों?

- सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिस्सा लिया।

मुख्य बिन्दु:

- **मुख्य अतिथि :** केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह।
- इस समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया।
- **सहकारी समितियाँ :** राजस्थान में 42,000 से अधिक सहकारी समितियाँ हैं, जिनसे 1.35 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। वहीं, राज्य में 'सहकार सदस्यता अभियान' के तहत 8.90 लाख नवीन सदस्यों को सहकारी समितियों में जोड़ा गया।

- **विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना :** इस योजना के अंतर्गत राज्य में 200 गोदाम स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 120 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। राजस्थान इस योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है।
- **इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (e-PACS) :** राजस्थान में e-PACS के प्रथम चरण में 5,646 पैक्स को e-PACS बनाया जा चुका है। इन e-PACS के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेनदेन हुए हैं, जो पूरे देश के कुल ट्रांजेक्शन का लगभग एक तिहाई है और देश में सबसे ज्यादा हैं।
- **e-PACS संख्या :** इलेक्ट्रॉनिक पैक्स (e-PACS) की संख्या के मामले में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है।
- e-PACS ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने वाली सहकारी ऋण समितियों (PACS) का डिजिटल और उन्नत रूप है।
- **मल्टीपरपज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (M-PACS) :** प्रत्येक पंचायत में सहकारी समिति गठन की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राजस्थान में 5,279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है।
- **BBSSL सदस्यता में प्रथम :** भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की सदस्यता सूची में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- नई दिल्ली में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान राजस्थान को कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न सौगातें दी गई; जैसे -

1. 10 नए अन्न भंडारण गोदामों का शिलान्यास।
2. 50 गोदामों का लोकार्पण।
3. 100 गोदामों को राज्य भंडारण निगम को हस्तांतरित किया गया।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:

Q.1 सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया?

A. विज्ञान भवन, नई दिल्ली

B. भारत मंडपम, नई दिल्ली

C. जयपुर सचिवालय

D. राष्ट्रपति भवन

Q2. विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने गोदाम स्वीकृत किए गए हैं?

A. 100

B. 150

C. 200

D. 250

Q3. विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन-सा स्थान है?

A. प्रथम

B. द्वितीय

C. तृतीय

D. चतुर्थ

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट – 2024 में राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय (ORGI) द्वारा 'नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट – 2024' जारी की गई।

SERVICES

मुख्य बिन्दु:

- यह रिपोर्ट भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण, गिरती प्रजनन दर और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के एक ऐतिहासिक मोड़ को दर्शाती है।
- **कुल प्रजनन दर (TFR) :** भारत की राष्ट्रीय TFR गिरकर 1.9 पर आ गई है, जो कि जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। यह लगातार पाँचवाँ वर्ष है, जब भारत इस स्तर से नीचे बना हुआ है।
- **अशोधित जन्म दर (CBR) :** राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित जन्म दर घटकर 18.3 (प्रति 1,000 जनसंख्या पर) हो गई है, जो 2014 में 21.0 थी। राज्यों में सबसे अधिक जन्म दर बिहार (26.8) में और सबसे कम केरल में है।

- **अशोधित मृत्यु दर (CDR) :** भारत की राष्ट्रीय मृत्यु दर 6.4 (प्रति 1,000 जनसंख्या पर) पर स्थिर बनी हुई है।
- **शिशु मृत्यु दर (IMR) :** बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो घटकर 24 (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर) हो गई है। राज्यों में केरल में सबसे कम (8) है।

राजस्थान का प्रदर्शन:

- **प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर :** राजस्थान देश के उन 6 राज्यों में शामिल है, जिनकी कुल प्रजनन दर (TFR) प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से ऊपर बनी हुई है।
- **99.5 प्रतिशत प्रसव अस्पतालों में :** वर्ष 2019 में जहाँ केवल 88.7 प्रतिशत महिलाओं की डिलीवरी अस्पतालों में होती थी, वह 2024 में बढ़कर 99.5 प्रतिशत हो गई है।
- **निवास स्थान पर जन्म के समय लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिला):**

राजस्थान (कुल)	917
ग्रामीण	913
शहरी	931

- **राजस्थान में आयु-विशिष्ट प्रजनन दर (ASFR) :** प्रति 1,000 महिलाओं पर जीवित बच्चों के जन्म की संख्या।

आयु-वर्ग (वर्ष में)	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
ASFRs	10.3	133.4	167.0	96.9	37.1	11.7	6.2

शिक्षा के स्तर के अनुसार 15-49 आयु वर्ग में महिला जनसंख्या का प्रतिशत (राजस्थान)

संकेत	निरक्षर	कुल साक्षर	बिना किसी औपचारिक शिक्षा के	प्राथमिक से नीचे	प्राथमिक	माध्यमिक	कक्षा - X	कक्षा - XII	स्नातक और उससे ऊपर
राजस्थान (आँकड़े प्रतिशत में)	13.0	87.0	5.0	7.2	15.5	19.4	15.8	13.3	10.9

ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना के नए दिशा-निर्देश-2026

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राज्य सरकार ने राजस्थान के ब्रज क्षेत्र (मुख्यतः भरतपुर और करौली) में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय विरासत को सहेजने के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना के नए दिशा-निर्देश-2026 लागू किए हैं।

मुख्य बिन्दु:

- इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग की ओर से भरतपुर और करौली जिले के चिह्नित ब्लॉक्स में बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ किया जाएगा।
- इस योजना का मुख्य फोकस श्री गिरिराजजी की 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर रहेगा।
- योजना के अंतर्गत 84 कोस परिक्रमा मार्ग का कायाकल्प, आधुनिक सुविधाएँ और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परिक्रमा मार्ग और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड:

- मुख्यालय : जयपुर।
- कार्यक्षेत्र : भरतपुर और करौली
- प्रशासनिक विभाग : पर्यटन विभाग, राजस्थान।

✂️ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**सहकार वन : सुमेल गाँव** ■ सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सुमेल गाँव में बनने वाले 'सहकार वन' का वर्चुअल भूमि पूजन किया। ■ इस वन की स्थापना अमूल और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) द्वारा की जाएगी। ■ **विस्तार :** 64 एकड़ जमीन पर। ■ मियावाकी और सामान्य प्रणाली से इस वन में खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम आदि वृक्ष लगाए जाएंगे। **प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न** **Q1. निम्नलिखित में से किस गाँव को राज्य के पहले 'सहकार वन' के रूप में विकसित किया जाएगा?** (a) सवाईपुरा (पाली) (b) सुमेल गाँव (जयपुर) (c) मंडावा (झुंझुनू) (d) धनौरा (धौलपुर)
2.	**डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम : अजमेर** ■ हाल ही में, विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पंचशील विजयाराजे नगर के निकट निर्माणाधीन मल्टीपरपज स्टेडियम का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राष्ट्रीय परिदृश्य

चांगपा समुदाय

चर्चा में क्यों?

- लद्दाख प्रशासन ने पश्मीना मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और चांगपा चरवाहा समुदाय की आजीविका को बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं।

मुख्य बिन्दु:

चांगपा

- लद्दाख के चांगथांग पठार में निवास करने वाला एक अर्ध-खानाबदोश पशुपालक समुदाय।
- ये मुख्य रूप से चांगथांग शीत रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य में निवास करते हैं।
- स्वदेशी चांगथांगी (चांगरा) बकरियों का पालन-पोषण करें , जो विश्व प्रसिद्ध पश्मीना (कश्मीरी) ऊन का उत्पादन करती हैं ।
- भारत में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में मान्यता प्राप्त।

UTKARSH CIVIL SERVICES

इतिहास एवं संस्कृति

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्य बिन्दु:

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (1901 - 1953)

- कलकत्ता में जन्मे, उन्होंने 1926 में इंग्लिश बार में शामिल होने के बाद बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की।
- 1934 में 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने।
- 1929 में बंगाल विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए।

प्रमुख योगदान

- जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया।
- उन्हें 'संसद का शेर' की उपाधि दी गई थी।
- 1940 में, वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बने।
- उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की (1951) और इसके पहले अध्यक्ष बने।
- पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य।

MCQ:

Q. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे वर्ष 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने थे।
2. वे वर्ष 1940 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बने।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

योजनाएँ एवं नीतियाँ

क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)– संशोधित UDAN लॉन्च

चर्चा में क्यों?

- क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) – संशोधित UDAN लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 25 मार्च 2026 को अनुमोदित इस योजना का उद्देश्य विमानन-आधारित विकास को गति देना और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को आगे बढ़ाना है।

मुख्य बिन्दु:

संशोधित उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना

- **अवधि:** 10 वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक)

आवश्यक घटक:

- **हवाई अड्डों का विकास (पूँजीगत व्यय):** मौजूदा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डों का विकास करना।
- **संचालन एवं रखरखाव सहायता:** लगभग 441 आरसीएस-ओनली हवाई अड्डों के लिए 3 वर्षों तक।
- **200 आधुनिक हेलीपैड का विकास:** पहाड़ी, दूरस्थ, द्वीपीय और महत्वाकांक्षी क्षेत्रों में अंतिम-मील कनेक्टिविटी और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार के लिए।
- **व्यवहार्यता अंतर निधि:** क्षेत्रीय मार्गों को बनाए रखने के लिए एयरलाइन ऑपरेटरों को 10 वर्षों में ₹10,043 करोड़ की सहायता।
- **आत्मनिर्भर भारत विमानन:** दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में विमानन क्षमता को मजबूत करने के लिए स्वदेशी विमानों की खरीद को बढ़ावा देना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

उड़ान योजना

- **प्रारंभ:** अक्टूबर, 2016 (राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) 2016 के अंतर्गत परिकल्पित)
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्र योजना।
- **मंत्रालय:** नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)।
- **उद्देश्य:** हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाकर तथा टियर-2 और टियर-3 शहरों से कनेक्टिविटी को मजबूत करके विमानन का लोकतंत्रीकरण करना।

MCQ:

Q. 'उड़ान' (UDAN) योजना निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारी योजना है?

(A) केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)

(B) केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)

(C) राज्य प्रायोजित योजना

(D) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) योजना

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA)

चर्चा में क्यों?

- भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता (बीआईए) लागू हो गया है। यह समझौता भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी), 1996 का स्थान लेता है, जिसे 2017 में समाप्त कर दिया गया था।

मुख्य बिन्दु:

- इसका उद्देश्य निवेशकों के संरक्षण और सरकारों के विनियमन के संप्रभु अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखते हुए निवेश को बढ़ावा देना है।
- संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन (1969) के तहत , "संधि" और "समझौते" के बीच कोई ठोस कानूनी अंतर नहीं है ।

बीआईटी

- **परिभाषा:** ये दो देशों के बीच पारस्परिक समझौते होते हैं जो एक-दूसरे के क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं ।
- **उद्देश्य:** ये निवेशकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने और एक स्थिर निवेश वातावरण बनाने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून:** बी.आई.टी. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क़ानून के अंतर्गत सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत् दायित्वों के प्राथमिक स्रोतों के रूप में आते हैं।
- बजट 2025-26 में, सरकार ने बीआईटी ढाँचे की समीक्षा की घोषणा की।

भारत-इजराइल बीआईटी

- **निवेश संरक्षण:** यह दोनों देशों के निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों की रक्षा करता है।
- **सशस्त्र संघर्ष के दौरान मुआवजा:** युद्ध, सशस्त्र संघर्ष या नागरिक अशांति के कारण नुकसान झेलने वाले निवेशकों को मुआवजे के संबंध में गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार प्राप्त होगा।

- **नियमन का अधिकार:** यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण के लिए नियमन करने के सरकार के अधिकार को संरक्षित करता है।
- **निवेशक-राज्य विवाद निपटान:** यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने का एक तंत्र प्रदान करता है।

MODEL MAINS QUESTION:

Q. "हाल ही में लागू हुआ भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA) निवेशकों के संरक्षण और सरकारों के विनियमन के संप्रभु अधिकार के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित करने का प्रयास है।" इस कथन की समीक्षा करते हुए भारत-इजराइल आर्थिक संबंधों पर इसके संभावित प्रभावों की विवेचना कीजिए।

UTKARSH CIVIL SERVICES

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

हायाबुसा2 मिशन

चर्चा में क्यों?

- जापान के हायाबुसा 2 यान ने अपने विस्तारित मिशन के दौरान एक क्षुद्रग्रह के पास से सफलतापूर्वक उड़ान भरी।

मुख्य बिन्दु:

Hayabusa2

- जापान की क्षुद्रग्रह नमूना-वापसी मिशन, जिसे जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) द्वारा विकसित किया गया है।
- क्षुद्रग्रह छोटे चट्टानी या धात्विक पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्रग्रह पेटी में पाए जाते हैं।

MCQ:

Q. 'हायाबुसा2' मुख्य रूप से किस प्रकार का अंतरिक्ष मिशन है?

(A) चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन

(B) मंगल ग्रह कक्षीय मिशन

(C) क्षुद्रग्रह नमूना-वापसी (Asteroid Sample-Return) मिशन

(D) सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन

विज्ञान प्रौद्योगिकी

सब-ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स (SOLVE)

चर्चा में क्यों?

- इसरो ने गगनयान मिशन के लिए महत्त्वपूर्ण पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट किया। सब-ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स (SOLVE) सॉलिड मोटर का सफल परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा स्थित स्थैतिक परीक्षण सुविधा में किया गया।

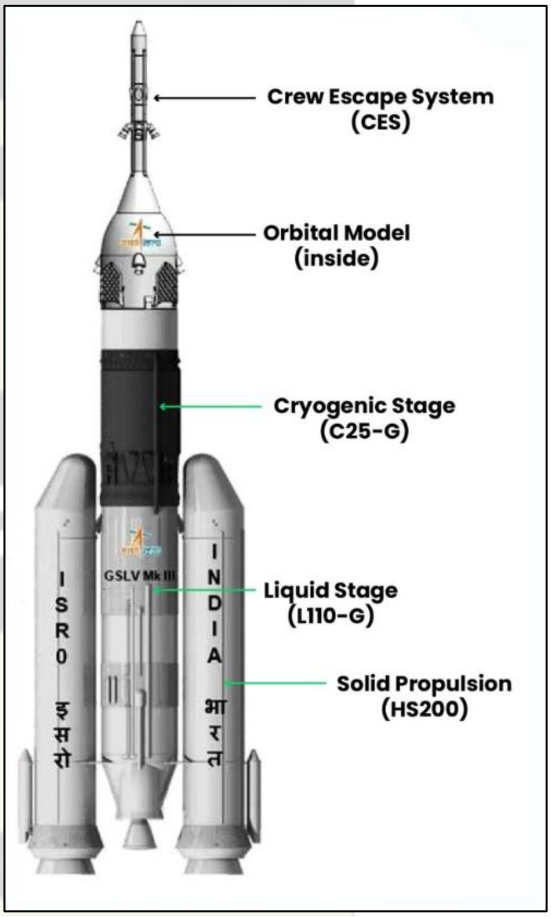

मुख्य बिन्दु:

- इसरो एकीकृत पैराशूट परीक्षण करने के लिए एक परीक्षण मंच के रूप में सॉलिड मोटर आधारित सॉल्व विकसित कर रहा है।

SOLVE

- **उद्देश्य:** यह गगनयान मिशन क्रू मॉड्यूल की पैराशूट प्रणाली को मान्य करने के लिए एक परीक्षण मंच के रूप में कार्य करेगा ।
- **कार्य:** क्रू मॉड्यूल को 10-17 किमी तक ले जाता है, जिसके बाद 10 पैराशूट का उपयोग करके अलग होकर समुद्र में उतरता है।
- **घटक:** सॉलिड मोटर को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) स्ट्रैप-ऑन मोटर से संशोधित करके बनाया गया है।

गगनयान मिशन

- भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में भेजना है, जिसके बाद भारतीय जलक्षेत्र में सुरक्षित लैंडिंग होगी।
- गाइनोइड (महिला रोबोट) व्योममित्र गगनयान का पहला मानव रहित मिशन शुरू करेगी।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक

चर्चा में क्यों?

- ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स (जीपीआई) में भारत की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में एक पायदान नीचे गिरकर 125वें स्थान पर आ गई है।

मुख्य बिन्दु:

ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स

- यह इस बात का मूल्यांकन करता है कि पासपोर्ट नागरिकों को यात्रा करने, निवेश करने, सुरक्षित रूप से रहने और वैश्विक अवसरों तक पहुँचने में कितनी प्रभावी ढंग से सक्षम बनाता है।
- **प्रकाशक :** ग्लोबल सिटिजन सॉल्यूशंस
- इसमें 200 देश शामिल हैं ।
- पासपोर्ट की मजबूती का आकलन करने के लिए तीन मुख्य स्तंभों (बेहतर गतिशीलता, निवेश क्षमता और जीवन की गुणवत्ता) और 15 संकेतकों का उपयोग किया जाता है।

MCQ:

Q. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष (हालिया रिपोर्ट में) ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है?

(A) रैंकिंग में 5 पायदान का सुधार हुआ है।

(B) रैंकिंग में एक पायदान की गिरावट आई है।

(C) रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(D) रैंकिंग में 10 पायदान की गिरावट आई है।